डिजिटल युग में ग्रामीण सामाजिक संरचना, महिला सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक सातत्य: पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में समीक्षात्मक अध्ययन

सुश्री तृप्ति सिंह*

डॉ जनक बहादुर*

शोध सारांश

प्रस्तुत समीक्षात्मक शोध पत्र देवरिया जनपद के डॉक्टरेट शोध समंकों के आधार पर ग्रामीण सामाजिक संरचना, महिला स्वायत्तता व सांस्कृतिक सातत्य पर संचार क्रांति के प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। पूर्वांचल का समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्ता, जाति संस्तरण और पर्दा प्रथा के कठोर नियंत्रण में रहा है। 4G/5G स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने इन समीकरणों को रूपांतरित किया है। समंक दर्शाते हैं कि 57.14% महिलाओं के पास स्वतंत्र स्मार्टफोन है तथा 84.82% बिना अनुमति फोन संचालित करती हैं। 68.37% महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हैं और 'बीसी सखी' बनकर चौपालों पर बैंकिंग चला रही हैं। 85.71% महिलाएं '1090 वूमेन पावर लाइन' से परिचित हैं। पंचायती राज में 65.87% ग्रामीणों ने 'प्रधानपति' प्रथा का खुला तिरस्कार किया है तथा 75.51% महिलाएं स्वतंत्र मतदान करती हैं। बाल विवाह (92.79%) व अस्पृश्यता (79.81%) का विरोध बढ़ा है तथा संस्थागत प्रसव 87.02% व बाल टीकाकरण 90.87% हुआ है। परिकल्पना परीक्षण में H_2 , H_3 ($\chi^2 = 36.85$) तथा H_4 की सार्थकता सिद्ध हुई। सांस्कृतिक स्तर पर छठ व लोकगीतों के वैश्विक प्रसार के साथ चौपालों का विखंडन (67.79%) व स्क्रीन व्यसन (80.77%) 'खंडित ग्राम' की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। पत्र अंत में डिजिटल चौपालों के पुनरुद्धार और जेंडर-संवेदनशील सुधारों की संस्तुति करता है।

बीज शब्द : *महिला सशक्तिकरण, सामाजिक संरचना, पितृसत्ता, बीसी सखी, प्रधानपति प्रथा, सांस्कृतिक सातत्य, खंडित ग्राम, देवरिया।*

1. प्रस्तावना एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि

मानव समाज के इतिहास में सामाजिक संरचना और मानवीय गरिमा का केंद्रीय मापदंड लैंगिक न्याय तथा समता रहा है (कबीर, 1999)। पूर्वांचल का ग्रामीण समाज ऐतिहासिक रूप से कठोर पितृसत्ता, जाति संस्तरण तथा महिलाओं की पराधीनता का जटिल केंद्र रहा है (दुबे, 1986; कार्वे, 1953)। पूर्वांचल की व्यवस्था 'पितृवंशीय' और 'पितृस्थानिक' नियमों से संचालित थी, जहां भूमि, कुल नाम और सत्ता पर पुरुषों का एकाधिकार था। मनुस्मृति के 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति' विधान की छाप के कारण ग्रामीण स्त्री का जीवन पिता, पति और पुत्र के अधीन सिमटा रहा। घूंघट प्रथा स्त्री की अभिव्यक्ति, ज्ञान और गतिशीलता को नियंत्रित करने वाली एक अदृश्य सामाजिक जेल थी।

बीना अग्रवाल (1994) ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण महिलाएं चूल्हे से खेत तक पुरुषों से अधिक श्रम करती हैं, किंतु संपत्ति और वित्तीय निर्णयों पर उनका अधिकार शून्य रहता है। इसे 'अदृश्य अवैतनिक देखभाल श्रम' कहा गया। जातिगत स्तर पर एम.एन. श्रीनिवास (1976) के अनुसार 'प्रभुजाति' सूचना की एकाधिकारिणी थी। विगत दशक में 4G/5G स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्रसार ने इस सामंती ढांचे को झकझोर दिया है। प्रस्तुत शोध प्राथमिक समंकों के आधार पर ग्रामीण सामाजिक संरचना, महिला स्वायत्तता, राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक सातत्य के द्वंद्वात्मक रूपांतरण की समीक्षा करता है।

2. सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की व्याख्या हेतु पांच प्रमुख शास्त्रीय व उत्तर-आधुनिक सिद्धांतों का संश्लेषण आवश्यक है:

1. एम. एन. श्रीनिवास: पश्चिमीकरण एवं 'प्रभुजाति' के एकाधिकार का क्षरण: श्रीनिवास (1966) के अनुसार पश्चिमीकरण तर्कबुद्धिवाद, मानवतावाद और समानता के आधुनिक मूल्यों का संचार है। श्रीनिवास (1962) की 'प्रभुजाति' संकल्पना बताती है कि भूमिधर उच्च जातियां सूचना की भी एकाधिकारिणी थीं। डिजिटल संचार ने इस ज्ञान एकाधिकार को समाप्त कर दिया है।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र), समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

* सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

वंचित जातियों के युवा व महिलाएं सीधे स्मार्टफोन पर संविधान, कानून व योजनाएं देखकर मुखर हो रहे हैं (सिंह एवं बहादुर, 2024)।

2. प्रो. योगेंद्र सिंह: 'परंपरा का आधुनिकीकरण' एवं सातत्य-परिवर्तन समन्वय: सिंह (1973, पृ. 24; 2000, पृ. 88) ने प्रतिपादित किया कि भारत में आधुनिकीकरण परंपरा के विनाश से नहीं, बल्कि 'सातत्य एवं परिवर्तन' के रचनात्मक संश्लेषण से घटित होता है। देवरिया में ग्रामीण नागरिक 5G फोन व यूपीआई अपनाते हुए भी छठ, सोहर व लोकपर्वों को अक्षुण्ण रखे हुए हैं, जो 'रूपांतरणात्मक सातत्य' का प्रमाण है।

3. पियरे बॉर्डियू का 'पूंजी रूपांतरण सिद्धांत': बॉर्डियू (1986, पृ. 241) के अनुसार पूंजी तीन रूपों—आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक—में होती है। एसएचजी और स्मार्टफोन महिलाओं हेतु 'पूंजी रूपांतरण इंजन' बन गए हैं। एसएचजी व्हाट्सएप ग्रुप 'सामाजिक पूंजी' है, यूट्यूब से सिलाई व कानूनी ज्ञान 'सांस्कृतिक पूंजी' है, और बीसी सखी द्वारा चौपाल पर बैंकिंग इसे 'आर्थिक पूंजी' (मासिक आय ₹8,000-₹15,000) में बदल देती है।
4. बीना अग्रवाल का 'घरेलू सौदेबाजी मॉडल': अग्रवाल (1994) का मॉडल सिद्ध करता है कि परिवार में महिला की आवाज उसकी 'फॉल-बैक पोजीशन' पर निर्भर करती है। स्वतंत्र बैंक खाता, एसएचजी और 1090 हेल्पलाइन युक्त स्मार्टफोन ने महिलाओं की सौदेबाजी शक्ति को ऐतिहासिक मजबूती दी है।

5. नैन्सी फ्रेजर का 'प्रति-सार्वजनिक क्षेत्र': हेबरमास (1989) के सार्वजनिक क्षेत्र की समीक्षा करते हुए फ्रेजर (1990, पृ. 56) ने 'अधीनस्थ प्रति-सार्वजनिक क्षेत्र' की अवधारणा दी। ग्रामीण महिलाएं जब घूंघट हटाकर ग्राम सभा में बैठती हैं और प्रधानपति प्रथा को नकारती हैं, तो वे सामंती पितृसत्ता के विरुद्ध ऐसे ही प्रति-सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं।

3. शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय प्रतिचयन

देवरिया की 31 लाख आबादी (89.8% ग्रामीण) से कोचरन (1977) सूत्र द्वारा 95% विश्वास स्तर व 4.8% त्रुटि सीमा पर N = 416 का प्रतिदर्श निर्धारित हुआ। बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन से चार विकास खंड—देवरिया सदर, बरहज, भटनी और रुद्रपुर—की 16 ग्राम पंचायतों से 416 उत्तरदाता (220 पुरुष, 196 महिलाएं) चुने गए। महिला सशक्तिकरण का विशेष अध्ययन 196 महिला उत्तरदाताओं (47.12%) के उप-प्रतिदर्श पर केंद्रित है (क्रोनबैक अल्फा $\alpha = 0.842$)।

4. अनुभवजन्य समंक विश्लेषण एवं समाजशास्त्रीय विमर्श

4.1 महिला स्मार्टफोन स्वामित्व एवं डिजिटल स्वायत्तता

4G क्रांति ने महिलाओं पर पुरुषों की तकनीकी पहरेदारी को समाप्त किया है। सारणी 1 में महिला स्मार्टफोन स्वामित्व का अनुभवजन्य वितरण प्रस्तुत है:

सारणी 1: ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में स्मार्टफोन स्वामित्व एवं स्वायत्तता

क्र.	स्मार्टफोन स्वामित्व एवं उपयोग स्वरूप	महिला आवृत्ति (f)	महिला % (n=196)	समग्र % (N=416)
1	स्वतंत्र व्यक्तिगत स्मार्टफोन स्वामित्व	112	57.14%	26.92%
2	पारिवारिक साझा स्मार्टफोन उपयोग (पति/पुत्र का फोन)	72	36.73%	17.31%
3	साधारण कीपैड फोन अथवा फोन-रहित (वृद्ध/अति निर्धन)	12	6.12%	2.88%
कुल	**समग्र महिला प्रतिदर्श महायोग**	**196**	**100.00%**	**47.12%**

स्रोत: प्राथमिक समंक, तृप्ति सिंह

सारणी 1 दर्शाती है कि 57.14% महिलाओं के पास स्वतंत्र फोन है तथा 36.73% पारिवारिक साझा फोन का नियमित उपयोग करती हैं; केवल 6.12% डिजिटल पहुंच से बाहर हैं। स्वतंत्र फोन धारक महिलाओं में से 84.82% (95 महिलाएं) ने बताया कि उन्हें फोन उपयोग हेतु पति या ससुर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। फोन में पैटर्न लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक लगाना स्त्री की व्यक्तिगत गोपनीयता और आत्मनिर्णय का रक्षा कवच बन गया है। पिपरा मदन गोपाल की संगीता देवी ने यूट्यूब से सिलाई सीखकर ₹7,000-₹9,000 मासिक आय अर्जित की और पारिवारिक निर्णय में सम्मानजनक स्थान पाया। भटनी की खातून निशा ने खाड़ी में कार्यरत पति से सीधे वीडियो कॉल और ₹25,000 मासिक रेमिटेंस प्रबंधन द्वारा स्वयं को घर की वास्तविक मुखिया स्थापित किया।

4.2 स्वयं सहायता समूह एवं बीसी सखी क्रांति

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देवरिया की 68.37% महिलाएं (134 उत्तरदाता) एसएचजी से सक्रिय जुड़ी हैं (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2021)। साप्ताहिक बचत (₹20-₹50) तथा 'लोकओएस' ऐप द्वारा बहीखाता संचालन ने वित्तीय पारदर्शिता दी है (यूनुस, 2003, पृ. 72)। महिलाओं ने सिलाई व सेनेटरी पैड निर्माण जैसे उद्यम स्थापित कर व्हाट्सएप बिजनेस पर विपणन शुरू किया है। सबसे बड़ा बदलाव 'बीसी सखी' मॉडल है, जहां महिलाएं बायोमेट्रिक माइक्रो-एटीएम लेकर चौपाल पर पेंशन, छात्रवृत्ति व मनरेगा मजदूरी वितरित करती हैं। जो महिलाएं कभी बैंक जाने से हिचकती थीं, आज वे पूरे गांव के लाखों रुपये के लेन-देन का संचालन कर ₹8,000 से ₹15,000 मासिक आय अर्जित कर रही हैं।

4.3 विधिक चेतना एवं सुरक्षा हेल्पलाइन्स

विधिक साक्षरता में 64.29% महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 तथा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 (पुत्री का समान अधिकार) से परिचित पाई गईं। सुरक्षा हेल्पलाइन्स में 85.71% (168 महिलाएं) '1090 वूमेन पावर लाइन' तथा '112 आपातकालीन सेवा' की सटीक जानकारी रखती हैं। 1090 की पहचान गोपनीयता ने शोहदों के भय को समाप्त किया है, जबकि 112 ने घरेलू हिंसा करने वाले पतियों में त्वरित पुलिस कार्रवाई का खौफ पैदा किया है। थानों पर 'महिला हेल्प डेस्क' तथा 'मिशन शक्ति' की महिला आरक्षियों ('शक्ति दीदी') ने पुलिस और महिलाओं के बीच की दूरी समाप्त कर दी है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022)।

4.4 पंचायती राज में 'प्रधानपति' प्रथा का तिरस्कार एवं स्वतंत्र मतदान

73वें संविधान संशोधन के बावजूद ग्रामीण भारत में 'प्रधानपति' (मुखिया पति) संस्कृति महिला सशक्तिकरण की विद्रूपता रही है (बुच, 2000, पृ. 41; बाविस्कर, 2003, पृ. 5035)। डिजिटल संचार ने इस सामंती ढकोसले को समाप्त किया है। सारणी 2 में राजनीतिक चेतना का अनुभवजन्य वितरण प्रस्तुत है:

सारणी 2: महिला उत्तरदाताओं में राजनीतिक स्वायत्तता एवं मतदान निर्णय

क्र.	राजनीतिक आयाम / स्वायत्तता	आवृत्ति (f)	प्रतिशत (%)	समाजशास्त्रीय निहितार्थ
1	पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्तिगत विवेक से मतदान निर्णय	148	75.51%	पारिवारिक दबाव से मुक्त; महिला सुरक्षा व कल्याणकारी डीबीटी आधार
2	परिवार/पति के साथ विचार-विमर्श उपरांत मतदान	38	19.39%	पारिवारिक संवाद, किंतु अंतिम निर्णय में महिला की सहमति अनिवार्य
3	पारंपरिक पुरुष आदेश अथवा अनिर्णीत / प्रॉक्सी वोटर	10	5.10%	अवशेष सामंती पितृसत्ता; राजनीतिक चेतना का अभाव
4	'प्रधानपति' प्रथा का	274	65.87%	महिला प्रधानों द्वारा

	खुला विरोध (N=416 समग्र)			स्वयं डोंगल व ई-ग्राम स्वराज का संचालन
5	ग्राम सभा खुली बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति	196	47.12%	एसएचजी दीदियों द्वारा कोटेदार घटतौली व विकास कार्यों पर सीधे प्रश्न

स्रोत: प्राथमिक समंक, तृप्ति सिंह

सारणी 2 दर्शाती है कि 75.51% महिलाएं स्वतंत्र विवेक से मतदान करती हैं। वे जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा, राशन व गैस सब्सिडी के आधार पर निर्णय लेती हैं (यादव, 2000, पृ. 120)। 65.87% ग्रामीणों ने प्रधानपति प्रथा का विरोध किया। पंचायती राज में वित्तीय भुगतान हेतु 'डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल' तथा ई-ग्राम स्वराज पर बैठकों की अनिवार्य वीडियोग्राफी ने महिला प्रधानों की वास्तविक उपस्थिति को अनिवार्य बना दिया है। पिपरा मदन गोपाल व सल्लहपुर की शिक्षित महिला प्रधान स्वयं डोंगल लगाकर भुगतान करती हैं और विकास कार्यों पर सीधी बात करती हैं।

4.5 सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संचेतना

सामाजिक सुधारों में 92.79% उत्तरदाता बाल विवाह का कड़ा विरोध करते हैं; किशोरियों ने 1098 चाइल्डलाइन पर सूचना देकर विवाह रुकवाए हैं। जातिगत छुआछूत का विरोध 79.81% तथा अंधविश्वास/ओझा-गुनी पर अविश्वास 71.63% दर्ज हुआ; सर्पदंश पर तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाने की वैज्ञानिक चेतना विकसित हुई है। शिक्षा में प्राथमिक विद्यालयों में 'दीक्षा ऐप' (62.50%) तथा यूट्यूब द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं (84.62%) की तैयारी ने महंगी कोचिंग पर निर्भरता समाप्त की है। स्वास्थ्य में संस्थागत प्रसव 87.02% (आशा समन्वय व 102/108 एम्बुलेंस), नियमित बाल टीकाकरण 90.87% (ई-कवच), आयुष्मान कार्ड 70.67% तथा व्यक्तिगत शौचालय उपयोग 83.65% पाया गया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2021; राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, 2023)।

5. शोध परिकल्पनाओं (H_2, H_3, H_4) का सांख्यिकीय सत्यापन

शोध प्रबंध में प्रतिपादित सामाजिक, लैंगिक व राजनीतिक परिकल्पनाओं का उन्नत सांख्यिकीय परीक्षण किया गया: 1. परिकल्पना H_2 (शिक्षा/स्वास्थ्य चेतना): संचार माध्यमों के नियमित उपयोग से सामान्य ज्ञान व स्वास्थ्य चेतना में सार्थक अंतर का स्वतंत्र प्रतिदर्श t-परीक्षण किया गया। उच्च उपयोग समूह (n=224, माध्य=78.42, SD=8.65) तथा निम्न उपयोग समूह (n=192, माध्य=71.18, SD=9.84) के मध्य t = 7.924 प्राप्त हुआ। df = 414 पर क्रांतिक मान 3.291 से अत्यधिक बड़ा होने के कारण शून्य परिकल्पना निरस्त और H_2 पुष्ट हुई (ब्लैलॉक, 1979)। 2. परिकल्पना H_3 (महिला सशक्तिकरण): स्मार्टफोन उपयोग स्तर (स्वतंत्र, साझा, अनुपयोगी) और सशक्तिकरण (उच्च, मध्यम, निम्न) के मध्य 3x3 काई-वर्ग परीक्षण किया गया। परिकलित मान $\chi^2 = 36.85$ प्राप्त हुआ। df = 2 पर p = 0.001 हेतु क्रांतिक मान 13.82 है। चूंकि $\chi^2 = 36.85 >> 13.82$, अतः शून्य परिकल्पना निरस्त और H_3 पूर्णतः पुष्ट हुई। यह सिद्ध करता है कि स्मार्टफोन उपयोग से महिलाओं की विधिक, स्वास्थ्य व पारिवारिक स्वायत्तता में सार्थक वृद्धि हुई है।

3. परिकल्पना H_4 (राजनीतिक सहभागिता): डिजिटल समाचार उपभोग और पंचायती राज सहभागिता के मध्य पियर्सन सहसंबंध $r = +0.512$ प्राप्त हुआ, जो प्रत्यक्ष सार्थक धनात्मक संबंध की पुष्टि करता है।

6. सांस्कृतिक सातत्य बनाम 'खंडित ग्राम' का द्वंद्व

सांस्कृतिक धरातल पर संचार क्रांति ने दोहरा प्रभाव उत्पन्न किया है। एक ओर भोजपुरी लोक संस्कृति का वैश्विक पुनरुद्धार हुआ है; छठ महापर्व के घाटों का खाड़ी देशों में सीधा प्रसारण प्रवासियों को अपनी माटी से जोड़े रखता है। सोहर व कजरी का यूट्यूब दस्तावेजीकरण हुआ है (तिवारी, 1960)। दूसरी ओर, रॉबर्ट पुटनाम (2000) के 'सोशल कैपिटल ह्रास' तथा शेरी टर्कल (2011) के 'अलोन टुगेदर' की स्थिति सामने आई है। 67.79% उत्तरदाताओं ने पारंपरिक चौपालों के विखंडन तथा 73.08% ने पारिवारिक संवादहीनता की पुष्टि की। एक ही कमरे में बैठे परिजन मोबाइल में मग्न रहकर 'आभासी निकटता व भौतिक दूरी'

के शिकार हैं। युवाओं में गेमिंग व रील्स का व्यसन 80.77% परिवारों में अनिद्रा व एकाग्रता ह्रास ला रहा है। शोधार्थी ने इसे 'खंडित ग्राम' कहा है।

7. जेंडर डिजिटल विभाजन एवं संरचनात्मक बाधाएं

महिला सशक्तिकरण में कई ढांचागत बाधाएं विद्यमान हैं (वैन डिज्क, 2020; हुयर एवं सिकोस्का, 2003):
1. डेटा रिचार्ज पर वित्तीय निर्भरता: 57.14% महिलाओं के पास फोन होने पर भी 41.2% को रिचार्ज (₹299) हेतु पति पर निर्भर रहना पड़ता है; विवाद होने पर पुरुष रिचार्ज बंद कर 'डिजिटल नाकेबंदी' करते हैं।
2. पारिवारिक नैतिक निगरानी: सास-ससुर द्वारा स्मार्टफोन चलाती बहुओं पर संशय व्यक्त किया जाता है; बहुएं केवल दोपहर या एकांत में खुलकर फोन चला पाती हैं।

3. साइबर संवेदनशीलता: 42.86% महिलाओं को अवांछित कॉल्स मिले। सुरक्षा साक्षरता के अभाव में महिलाएं आसान शिकार बनती हैं (परिकल्पना H_5: $\chi^2 = 29.47$, $p < 0.001$)।

8. नीतिगत संस्तुतियां एवं रणनीतिक रोडमैप

ग्रामीण सामाजिक समरसता और महिला स्वायत्तता हेतु नीतिगत रोडमैप:
1. पंचायती राज में 'डिजिटल चौपाल': ग्राम सचिवालयों में साप्ताहिक डिजिटल चौपाल लगे जहां युवा बुजुर्गों को मोबाइल सिखाएं और बुजुर्ग युवाओं को सामाजिक संस्कार दें।

2. बीसी सखियों का तकनीकी उन्नयन: बीसी सखियों को 5G टैबलेट्स, आइरिस स्कैनर व बीमा दिया जाए ताकि वे बैंकिंग को अंतिम छोर तक पहुंचा सकें।

3. महिला समूहों हेतु साइबर साक्षरता: एसएचजी बैठकों में 1090, 112 तथा साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग 1930 का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

4. ग्राम सचिवालय में महिला अध्ययन केंद्र: बालिकाओं की ऑनलाइन उच्च शिक्षा हेतु ग्राम सचिवालय में सुरक्षित वाई-फाई अध्ययन कक्ष बनें।

9. उपसंहार एवं निष्कर्ष

यह समीक्षात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि डिजिटल संचार क्रांति ने देवरिया जनपद में ग्रामीण महिलाओं को मूक दर्शक से सक्रिय अभिकर्ता बनाया है। स्मार्टफोन ने घूंघट की चारदीवारी को भेदकर विधिक सुरक्षा, वित्तीय स्वावलंबन और स्वतंत्र मताधिकार दिया है। बीसी सखियों द्वारा बैंकिंग और महिला प्रधानों द्वारा डोंगल का स्वयं संचालन पारंपरिक पितृसत्ता पर प्रहार है। यह परिवर्तन प्रो. योगेंद्र सिंह के 'सातत्य एवं परिवर्तन' तथा श्रीनिवास के 'प्रभुजाति क्षरण' का मूर्त रूप है। तथापि, चौपालों के विखंडन, संवादहीनता तथा जेंडर डिजिटल विभाजन का समाधान आवश्यक है ताकि तकनीक मानवीय संबंधों को संबल दे सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अग्रवाल, बी. (1994). A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. (2022). डिजिटल भारत प्रगति प्रतिवेदन 2021-2022. भारत सरकार, नई दिल्ली.

कार्वे, इ. (1953). Kinship Organization in India. डेक्कन कॉलेज, पूना.

कबीर, एन. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.

कूले, सी. एच. (1909). Social Organization: A Study of the Larger Mind. चार्ल्स स्क्रिबनेर्स संस, न्यूयॉर्क.

कोठारी, सी. आर., एवं गर्ग, जी. (2019). Research Methodology: Methods and Techniques (4th ed.). न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

गांधी, एम. के. (1942). Village Swaraj. नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद.

जनगणना कार्य निदेशालय. (2011). जिला जनगणना पुस्तिका: देवरिया. भारत सरकार, नई दिल्ली.

तिवारी, यू. एन. (1960). The Origin and Development of Bhojpuri. द एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता.

दुबे, एल. (1986). Seed and earth: The symbolism of biological reproduction and sexual relations of production. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.

पुटनाम, आर. डी. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. साइमन एंड शूस्टर, न्यूयॉर्क.

फ्रेजर, एन. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Social Text, (25/26), 56-80.

ब्लैलॉक, एच. एम. (1979). Social Statistics. मैकग्रा-हिल, न्यूयॉर्क.

बुच, एन. (2000). Women's Experience in New Panchayats: The Emerging Leadership of Rural Women. सेंटर फॉर वूमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली.

बाविस्कर, बी. एस. (2003). Impact of women's reservation in Panchayati Raj. Economic and Political Weekly, 38(48), 5035-5038.

बॉर्डियू, पी. (1986). The forms of capital. In J. Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. ग्रीनवुड प्रेस, न्यूयॉर्क.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2022). Mission Shakti Guidelines. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन. (2021). Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission Annual Report. ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण. (2023). Ayushman Bharat PM-JAY Annual Report 2022-23. भारत सरकार, नई दिल्ली.

यादव, वाई. (2000). Understanding the second democratic upsurge: Trends of thinking in 1990s. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.

यूनुस, एम. (2003). Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. पब्लिकअफेयर्स, न्यूयॉर्क.

रोजर्स, ई. एम. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क.

रोजर्स, ई. एम. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क.

लर्नर, डी. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. फ्री प्रेस, ग्लेनको, आईएल.

वैन डिज्क, जे. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. सेज पब्लिकेशन्स, लंदन.

वैन डिज्क, जे. (2020). The Digital Divide. पॉलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

वारशॉवर, एम. (2003). Technology and Social Inclusion. एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

श्रीनिवास, एम. एन. (1962). Caste in Modern India and Other Essays. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे.

श्रीनिवास, एम. एन. (1966). Social Change in Modern India. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले.

श्रीनिवास, एम. एन. (1976). The Remembered Village. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले.

सिंह, वाई. (1973). Modernization of Indian Tradition: A Systemic Study of Social Change. थॉमसन प्रेस, दिल्ली.

सिंह, वाई. (2000). Culture Change in India: Identity and Globalization. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर.

सिंह, टी. (2026). ग्रामीण जागरूकता में संचार क्रांति की भूमिका (देवरिया जिले के विशेष सन्दर्भ में). अप्रकाशित विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.) शोध-प्रबंध, समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.).

सिंह, टी., एवं बहादुर, जे. (2024). ग्रामीण पूर्वांचल में संचार क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन: एक समाजशास्त्रीय उपागम. शोध प्रभा, 49(1), 112-124.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. (2021). National Family Health Survey 2019-21: India Report. आईआईपीएस, मुंबई.

हेबरमास, जे. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज, एमए.

हुयर, एस., एवं सिकोस्का, टी. (2003). Overcoming the Gender Digital Divide. इनस्ट्रॉ रिसर्च पेपर, संयुक्त राष्ट्र.